सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 211 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, मंगलवार 8 सितम्बर, 2026
मूल्य ₹ 3/-

छोटे-छोटे खर्चों से सावधान रहिये। एक छोटा सा छेद बड़े से जहाज को डुबा सकता है।
-बेंजामिन फ्रैंकलिन

तिहरा शतक नहीं लगा सके ईशान... 7 | मोदी कैबिनेट में जल्द, बड़ा... 3 | नीला रंग विशाल खुले आसमान... 2

हाय रे मॉबलिचिंग : मणिपुर के संगीत टीचर को गुंडो ने पीट-पीट कर मार डाला

मणिपुरी शिक्षक की हत्या ने गृहमंत्री शाह की पुलिस और राजधानी दिल्ली की सुरक्षा पर उठाया सवाल!

» अपराधों की राजधानी बनती दिल्ली गृहमंत्री की नाक के नीचे घटनाएं होता बवाल

» दिल्ली में कौन सुरक्षित : मॉब लिचिंग बनता फैशन जिसको चाहो पीटकर मार दो!

» 8 लोग गिरफ्तार घटना ने पकड़ा तूल आखिर क्या कसूर था टीचर का

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। रात का वक्त था। घर के बाहर शोर था। एक आदमी नीचे उतरा। उसने बस इतना कहा शोर मत करो। उसे क्या पता था कि जिस शोर को रोकने के लिए वह घर से बाहर निकला है वही शोर उसकी जिंदगी का आखिरी शोर बन कर रह जाएगा। मणिपुर के टीचर और शोर मचा रहे लोगों के बीच बहस हुई।

बात बढ़ी फिर हाथ चले मुट्ठियां तनी और एक आदमी पर बहुत से लोग टूट पड़े। वह बचने के लिए भागा लेकिन भीड़ ने पीछा नहीं छोड़ा वह अपने घर तक पहुंचा मगर मौत उसके पीछे पीछे घर में दाखिल हो चुकी थी। 54 वर्षीय मणिपुरी संगीत शिक्षक और कलाकार चोंगथम विक्रम सिंह अस्पताल पहुंचे लेकिन गंभीर चोटों के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और सात आरोपियों को गिरफ्तार तथा एक नाबालिग को पकड़े जाने की जानकारी दी है।

पूरी खबर हमारे 4PM चैनल पर उपलब्ध है

अमित शाह जी दिल्ली में कानून का खौफ किससे पूछकर खत्म हुआ?

सवाल बड़ा है जहां घटना हुई है वह कोई टूरदराज का कस्बा नहीं है यह दिल्ली है देश की राजधानी वही दिल्ली जहां संसद है प्रधानमंत्री का कार्यालय है गृह मंत्रालय है गृह मंत्री अमित शाह का कार्यालय है दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है सुरक्षा एजेंसियों का पूरा ढांचा है सीसीटीवी है पेट्रोलिंग है इंटेलिजेंस है। पुलिस कंट्रोल रूम है फिर भी एक नागरिक अपने घर के बाहर खड़े लोगों से सिर्फ इतना कहता है कि शोर कम करिए और कुछ देर बाद उसकी जान चली जाती है। तो सवाल बहुत सीधा है गृहमंत्रि अमित शाह बताए कि दिल्ली में कानून का खौफ किससे पूछकर खत्म हुआ? किसने इन लोगों को यह भरोसा दिया कि विवाद को बातचीत से नहीं, ताकत से सुलझाया जा सकता है? किसने यह भरोसा दिया कि अगर एक आदमी सामने खड़ा है तो कई लोग उस पर टूट सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल क्या दिल्ली में कानून आने से पहले भीड़ पहुंच रही है? विक्रम सिंह की मौत को किसी जातीय या नस्ली मकसद से जोड़ देना अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस ने भी कहा है कि ऐसा कोई मकसद अभी स्थापित नहीं हुआ है और जांच जारी है। लेकिन यह भी सच है कि उनकी मौत के बाद पूर्वोत्तर समुदाय में गुस्सा और असुरक्षा की भावना सामने आई है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया कि दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर के परिवार आखिर खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें।

राहुल ने उठाया दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल, गृह मंत्रालय को घेरा

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की दिल्ली में हुई मौत को लेकर राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह की हत्या जिस तरह हुई उसने दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि विक्रम सिंह अपने घर के बाहर हो रहे शोर को लेकर आपत्ति जताने के लिए बाहर निकले थे लेकिन उनके साथ मारपीट की गई और उनकी जान चली गई। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब राजधानी में अपने ही घर के बाहर एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर के परिवार खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे।

गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस जिम्मेदार

राहुल गांधी ने इस घटना को सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित न रखते हुए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी के मुताबिक खास तौर पर पूर्वोत्तर के लोगों को निशाना बनाए जाने की आशंकाओं से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र क्या कर रहा है इसका जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और विक्रम सिंह के परिवार के प्रति संवेदना जताई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी विक्रम सिंह की मौत को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस घटना को केवल शराब के नशे में हुई हिंसा या किसी एक रात की आपराधिक वारदात बताकर नजरअंदाज करना पर्याप्त नहीं होगा। उनका आरोप है कि लंबे समय से तेज आवाज में संगीत सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा और नियमों की अनदेखी जैसी घटनाओं पर पर्याप्त सख्ती नहीं होने से लोगों में कानून का डर कमजोर हुआ है। पवन खेड़ा ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भले ही सीधे सरकार के हाथ में न हो लेकिन कानून के प्रति लापरवाही का माहौल बनने की जिम्मेदारी से सरकार पूरी तरह अलग नहीं हो सकती। यानी राजनीतिक बहस अब सिर्फ यह नहीं है कि विक्रम सिंह के हत्यारे कौन हैं बल्कि सवाल यह भी है कि राजधानी में कानून का डर आखिर कितना बचा है और क्या हर नागरिक को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा?

घर के सामने शोर मचाने से मना कर रहे थे चोंगथम

मणिपुर के रहने वाले संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की बीती रात मॉबलिचिंग कर कुछ लोगों ने हत्या कर दी। हत्या करने का कारण सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने घर के सामने इक्टठा हुए लोगों से जोकि शराब पी रहे थे और शोर मचा रहे थे को कहीं और जाने के लिए कहा। चोंगथम दिल्ली के आश्रम इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। चोंगथम इंफाल के रहने वाले गिटारिस्ट और संगीतकार थे। वह रॉक बैंड्स का हिस्सा रह चुके है और पिछले कुछ वर्षों से काम नहीं कर रहे थे। वह कई वर्षों से संगीत प्रस्तुत करते रहे थे और संगीत शिक्षक भी थे। चोंगथम के बेटे याइफाबा और उनकी मां घटना के समय घर पर ही थे। याइफाबा ने बताया कि उन्होंने तेज आवाजें और सिंह के चीखने की आवाज सुनी। याइफाबा के मुताबिक जब उन्होंने दरवाजा खोला तो चार पांच लोगों को अपने पिता पर हमला करते देखा।

और यही सवाल सबसे खतरनाक है

अगर देश की राजधानी में रहने वाला नागरिक अपने घर में भी यह सोचने लगे कि बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं तो सरकार की सुरक्षा व्यवस्था का मतलब क्या रह जाता है? विक्रम सिंह कोई अपराधी नहीं थे। वह संगीत सिखाते थे वह वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे उन्होंने इस शहर में अपनी जिंदगी बनाई थी वह रात भी शायद बाकी रातों जैसी ही थी लेकिन एक छोटी सी आपत्ति ने हिंसा का रूप लिया और एक परिवार का संसार उजड़ गया।

सड़क पर अदालत, पुलिस उठाये लाश

यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह उस मानसिकता की कहानी है जिसमें कुछ लोगों को अचानक यह भ्रम हो जाता है कि सामने वाले की जिंदगी से बड़ी उनकी ताकत है। यही वह जगह है जहां मॉब लिंचिंग का भूत दिल्ली के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। मॉब लिंचिंग का मतलब सिर्फ यह नहीं कि किसी को भीड़ ने मार दिया। असली डर उस मानसिकता का है जिसमें भीड़ को भरोसा हो जाए कि कानून बाद में आएगा पहले हम फैसला करेंगे। आज विक्रम सिंह थे कल कोई और हो सकता है आज शोर का विरोध था कल रास्ते का विवाद हो सकता है आज लाठी डंडे घूसे चले कल हथियार भी उठ सकता है। सवाल यह नहीं कि दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया या नहीं सवाल यह है कि क्या कानून का डर इतना कमजोर हो गया है कि लोग पहले सड़क पर अदालत लगाएं और फिर पुलिस को लाश उठाने के लिए बुलाया जाए?

नीला रंग विशाल खुले आसमान का प्रतिनिधित्व करता है : सपा

» नेता बोले- जिसके नीचे हर कोई समान और जाति-आधारित भेदभाव से मुक्त है

» सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लखनऊ में आयोजित छात्रसभा के सम्मेलन में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसी नए ड्रेस कोड में दिखाई देंगे। सपा के पदाधिकारियों का दावा है कि नीला रंग इसलिए अपनाया गया है क्योंकि यह विशाल खुले आसमान का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके नीचे हर कोई समान और जाति-आधारित भेदभाव से मुक्त है। यह एक अलग बात है कि यह डॉ बीआर अंबेडकर का भी पसंदीदा रंग था। नीला रंग दलितों का भी रंग रहा है।

यह समुदाय अब समाजवादी पार्टी के पीडीए (पीडीए) एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। माना जा रहा है कि छात्र सभा के लिए नए ड्रेस कोड की औपचारिक घोषणा पार्टी नेतृत्व की ओर से अगले कुछ दिनों में लखनऊ में सपा मुख्यालय में आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में की जा सकती है। सपा के इस फैसले को महज संगठनात्मक बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके पीछे दलित और जेन-जी वोटरों तक पहुंच बनाने की राजनीतिक रणनीति भी मानी जा रही है। नई ड्रेस के जरिए पार्टी कॉलेज और विश्वविद्यालय की राजनीति में सक्रिय युवाओं तक एक राजनीतिक संदेश पहुंचाना चाहती है। नीले रंग को दलित अस्मिता और आंबेडकरवादी विचारधारा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सपा का यह प्रयोग दलित युवाओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने और उन्हें सपा के साथ जोड़ने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यानी छात्रसभा का बदला हुआ ड्रेस कोड सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं, बल्कि 27 से पहले सपा की युवा और दलित वोटरों को साधने की बड़ी राजनीतिक कवायद का संकेत भी माना जा रहा है।

नीले स्कार्फ में अखिलेश और शिवपाल

यह पहली बार नहीं है जब नीला रंग सपा के आधिकारिक रंगों में शामिल हो रहा है। हाल ही में 31 अगस्त को राज्य भर के पार्टी के जिला और शहर अध्यक्षों की बैठक के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सहित पार्टी के बड़े नेताओं को नीले स्कार्फ पहने हुए देखा गया, जिन पर पार्टी का चुनाव चिह्न साइकिल लाल रंग में प्रिंट था। नीला स्कार्फ पहले के लाल और हरे स्कार्फ से अलग था, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान लाल चेक वाले गमछे में बदल दिया गया था। जब नीले स्कार्फ के बारे में सवाल पूछा गया, तो पार्टी पदाधिकारियों ने उस सवाल को टाल दिया था।

युवाओं में लोकप्रिय रंग का चुनाव

सूत्रों के अनुसार, सपा नेतृत्व ने पार्टी की छात्र शाखा के सदस्यों को पार्टी के बाकी संगठनों से अलग एक विशिष्ट पहचान देने का फैसला किया है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि छात्र सभा के लोगो में इसके मूल तत्व, आकार और रंग योजना में लाल और हरा रंग बरकरार रखा गया है। पार्टी रणनीतिकारों का कहना है कि चूंकि छात्र सभा में ज्यादातर जेन जी के छात्र शामिल हैं, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने युवाओं के बीच लोकप्रिय रंग चुनने का फैसला किया।

सपा विधायक अतुल प्रधान हाउस अरेस्ट

उत्तर प्रदेश के मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने उनके घर पर नजरबंद कर दिया है। रात से ही उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैनात हैं। बताया जा रहा है कि अतुल प्रधान सहारनपुर जाने वाले समाजवादी पार्टी के 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। सपा का यह प्रतिनिधिमंडल आज सहारनपुर पहुंचकर मंडलायुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी हासिल कर अपनी रिपोर्ट पार्टी लाईकमान को सौंपेगा। अतुल प्रधान जब अपनी गाड़ी से घर से निकलने के लिए पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया और आगे जाने से रोक दिया। पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए सपा नेताओं को नजरबंद किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, सपा नेताओं का कहना है कि वे सहारनपुर जाकर पूरे मामले की जानकारी लेना चाहते हैं। अभी किसी और नेता के सहारनपुर पहुंचने की सूचना नहीं है।

जलभराव, जाम, बढ़ते टैक्स से सभी परेशान : फाखिर सिद्दीकी

सपा महानगर अध्यक्ष फाखिर सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा सरकार से जनता त्रस्त है। बारिश में जगह-जगह जलभराव, सड़कों पर जाम और बढ़े गृहकर व जलकर ने परेशानी बढ़ा दी है। लखनऊ महानगर की शहर स्तरीय बैठक में महामंत्री गौरव सिंह यादव ने कहा कि युवाओं ने सपा और भाजपा दोनों का कार्यकाल देखा है। अब युवा और वरिष्ठ मतदाता भाजपा के जुमलों में नहीं आएंगे। विकास, उन्नति और रोजगार के लिए सपा के पक्ष में मतदान करेंगे। बैठक में पूर्व एमएलसी डॉ. मधु गुप्ता, विधायक रविदास मेहरोत्रा और अरमान खान ने जनता के बीच सक्रिय रहने की बात कही। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बूथ व वार्ड स्तर पर जनता के बीच सक्रिय रहकर उनके कार्य कराने का संकल्प लिया।

ईशान को मायावती ने दी बड़ी जिम्मेदारी

» बसपा का युवा चेहरे के जरिये जेन-जी को साधने की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बसपा में आकाश की जगह ईशान को राजनीति में लाने की मायावती की रणनीति के पीछे जेन-जी को वजह माना जा रहा है। इसके जरिये मायावती ने यह संदेश दिया है कि पार्टी में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही आकाश को हटाए जाने से उपजी नाराजगी को भी कम करने की कवायद की गई है।

मायावती ने कई पदाधिकारियों का कद भी बढ़ाया है। हाल ही में पार्टी से बाहर किए गए रणधीर सिंह बेनीवाल की वापसी के बाद उनको पूर्व की तरह सहारनपुर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह नेशनल कोआर्डिनेटर रामजी गौतम और लालाराम को भी कई अन्य राज्यों का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा विपुल कुमार को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। सक्रिय राजनीति में आने से पहले ईशान आनंद अपने पिता आनंद कुमार का कारोबार संभाल रहे थे। उन्होंने भी अपने बड़े भाई आकाश आनंद की तरह लंदन में पढ़ाई की है। करीब 27 वर्षीय ईशान को मायावती ने पिछले साल अपने जन्मदिन पर सबसे मिलवाया था। इसके बाद से उनके राजनीति में आने के कयास लगने लगे थे। उनका विवाह नोएडा के कारोबारी की बेटी राधिका खन्ना से बीते वर्ष 24 अप्रैल को हरियाणा में हुई थी, जिसमें मायावती भी मौजूद थीं।

मायावती को रिपोर्ट करेंगे ईशान

दरअसल, बसपा में मायावती ने छोटे भतीजे ईशान आनंद को मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ईशान को उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। वह संगठन के कार्यों की समीक्षा के बाद मायावती को रिपोर्ट करेंगे। इस बदलाव के बाद पूर्व राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की वापसी मुश्किल हो गई है। वहीं, आकाश को राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाए जाने से उनके समर्थक मायूस हैं और सोशल मीडिया पर उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस ने नाजिला फिरदौस का दी बधाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस ने नाजिला फिरदौस को यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में पहले ही प्रयास में 99.6 परसेंटाइल प्राप्त कर जूनियर रिसर्च फेलोशिप की योग्यता हासिल करने पर बधाई दी है। कांग्रेस मेरठ के कारी इरफान ने कहा कि आपकी सफलता आपकी लगन, मेहनत और बुद्धिमत्ता का जीवंत प्रमाण है।

बता दें नाजिला वरिष्ठ कांग्रेस नेता अल्लू मियां की पोती और निहालगढ़ के ग्राम प्रधान मुहम्मद खलीक सिद्दीकी की सुपुत्री हैं। इस उपलब्धि से पूरे परिवार, अमेठी और कांग्रेस परिवार को गर्व हुआ है। आपने न केवल अपना बल्कि क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। अब आपका अगला लक्ष्य सिविल सेवा परीक्षा है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप वहाँ भी शानदार सफलता हासिल करेंगी। मेरठ कांग्रेस परिवार की ओर से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आप नई ऊँचाइयों को छूती रहें।

अरावली पैनल की ढील पर भड़के सीजेआई

» कमेटी की समय-सीमा बढ़ाने की मांग खारितज

» वे मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे : जस्टिस सूर्यकांत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

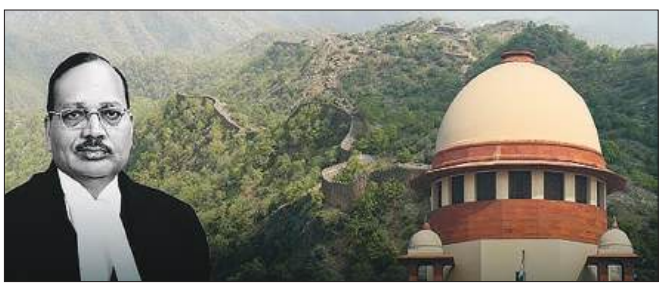

नई दिल्ली। अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान वैज्ञानिक परिभाषा तय करने के लिए गठित हाई-पावर कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा को 28 फरवरी, 27 तक बढ़ाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पैनल को दिन-रात काम करने और 30 नवंबर, 26 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट हर हाल में जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। CJI ने केंद्र की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, उन्हें साफ तौर पर मेरे रिटायरमेंट के बाद की तारीख मांगनी चाहिए थी ऐसा लगता है कि वे मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

जस्टिस कांत 9 फरवरी, 27 को पद छोड़ेंगे। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे, ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की डायरेक्टर जनरल कंचन देवी की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय पैनल को दिन-रात काम करने और नई समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आगे कोई समय नहीं बढ़ाया जाएगा।

बेंच ने अपने आदेश में कहा, हाई-पावर कमेटी ने शुरुआत में ही 28 फरवरी, 27 तक समय बढ़ाने की मांग की है। हालांकि, कोर्ट ने इस काम की जटिलता को माना और कमेटी को निर्देश दिया कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़े, वे खास मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपें। कोर्ट ने कहा कि इन रिपोर्टों से पूरी प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार किए बिना अलग-अलग सवालों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

जनता को गुमराह करने का प्रयास हो रहा : संजय सिंह

» आप नेता का कांग्रेस पर हमला, बोले- बना रही फर्जी टीम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस पर पार्टी के संगठन को लेकर भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन लोगों को आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव बताते हुए पार्टी में शामिल कराया है, उस नाम से आप के संगठन में ये पद मौजूद नहीं हैं। संजय सिंह ने पूरे मामले को कांग्रेस की राजनीतिक साजिश करार दिया।

संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ जगहों पर यह खबर चलाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक पांडेय, प्रदेश महासचिव संजय मिश्रा और कुछ अन्य लोग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए सवाल उठाया कि मीडिया को यह गलत जानकारी किसने उपलब्ध कराई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमांडो अशोक और प्रदेश महासचिव नीरज छौंकर हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि किसी दूसरे व्यक्ति को फर्जी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महासचिव बताकर पार्टी में शामिल कराना कांग्रेस की राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है।

मोदी कैबिनेट में जल्द, बड़ा फेरबदल

मंत्रियों की कुर्सियां हिलना तय, होगी विभागों की अदला बदली

- संगठन के बाद अब सरकार की बारी रिशफल की तैयारी
- पीएम मोदी के विदेश यात्रा से वापस लौटते ही बदलाव की संभावना !
- 70 पार के मंत्रियों की छुट्टी, महिलाओं की भागीदारी और युवा चेहरों पर फोकस
- पार्टी के भीतर बगावत, अपेक्षा और गुटबाजी को भी कंट्रोल करने की कवायद से देखा जा रहा है संभावित कैबिनेट फेरबदल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राजीनति में अक्सर ऐसा लगता है कि पूरा फिल्म का सेट तैयार है बस निर्देशक के एक्शन बोलने की देर है। दिल्ली में इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल दिखायी दे रहा है। बाहर सवालों की आग है और अंदर बेचैनी की तपिश।

सत्ता के गलियारों में बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा से भारत वापस लौटते ही क्या मंत्रिमंडल की कुर्सियां हिलेंगी क्या विभागों की अदला बदली होगी क्या कुछ पुराने चेहरों की जिम्मेदारी हल्की होगी और कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा और अगर फेरबदल हुआ तो सबसे बड़ा सवाल किसकी कुर्सी बचेगी और किसका मंत्रालय जाएगा

अचानक पैदा नहीं हुयी हैं कैबिनेट फेरबदल की खबरें

कैबिनेट फेरबदल की अटकलें अचानक पैदा नहीं हुई हैं। भाजपा संगठन में बदलाव के बाद अब केंद्र सरकार की टीम में बदलाव की चर्चाएं तेज हैं। अंदर से आती खबरों के मुताबिक युवाओं और महिलाओं को अधिक जगह देने 70 वर्ष से अधिक उम्र के कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी घटाने और मंत्रालयों के बोझ को पुनर्व्यवस्थित करने की बातें सामने आई हैं। यहां तक कि 6 से 7 सितंबर के आसपास संभावित फेरबदल की चर्चा भी चल रही है।

संदेश बाहर से नहीं घर के भीतर से आ रहा है

इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों की हो रही है एक नाम राजनाथ सिंह का है और नाम नितिन गडकरी क्या दोनों के मंत्रालय बदले जाएंगे? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि दोनों सरकार के सबसे महत्वपूर्ण और पहचान वाले चेहरों में हैं। आधिकारिक रूप से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय और नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे हैं। लेकिन सियासत में सवाल यह नहीं कि आज कौन किस कुर्सी पर बैठा है। सवाल यह है कि कल किस कुर्सी पर कौन बैठेगा? कुछ रिपोर्टों में गडकरी के विभाग में बदलाव अश्विनी वैष्णव को बड़ी जिम्मेदारी और नए चेहरों को शामिल किए जाने जैसी अटकलें सामने आई हैं। एक रिपोर्ट में 17 नए चेहरों तक की चर्चा है। लेकिन इनमें से किसी भी संभावित बदलाव को फिलहाल अंतिम फैसला मानना जल्दबाजी होगी। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक गणित छिपा है अगर फेरबदल होता है तो क्या यह केवल प्रशासनिक कवायद होगी? या 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक संदेश भी होगा? क्योंकि मंत्रिमंडल सिर्फ सरकार चलाने की मशीन नहीं होता। वह राजनीतिक संदेश भी होता है। किस राज्य को प्रतिनिधित्व मिला किस सामाजिक समूह को जगह मिली किस पीढ़ी को आगे किया गया किस पुराने चेहरे को किनारे किया गया किस मंत्री का मंत्रालय बदला गया और किस सांसद को पहली बार सत्ता के केंद्र में जगह मिली

सवाल सिर्फ मंत्रियों का नहीं है

राजनीति में अटकलें भी तब खबर बन जाती हैं जब उनके पीछे बेचैनी दिखायी देती है। और आज सवाल सिर्फ मंत्रियों का नहीं है सवाल उस राजनीतिक तापमान का है जिसमें मोदी सरकार को अपनी टीम फिर से सजाने की जरूरत महसूस हो रही है। एक तरफ युवाओं का गुस्सा है। जेनजी ने हाल के आंदोलनों में परीक्षा व्यवस्था भर्ती और रोजगार के सवालों को लेकर सड़कों पर अपनी ताकत दिखायी। यह वही पीढ़ी है जो भाषण से ज्यादा जवाब चाहती है और नारे से ज्यादा परिणाम। परीक्षा और रोजगार के मुद्दों पर हुए आंदोलनों ने सरकार के सामने यह चुनौती रख दी है कि युवा मतदाता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं व्यवस्था की विश्वसनीयता का हिसाब भी मांग सकता है। दूसरी तरफ किसान और रोजगार जैसे पुराने लेकिन अभी भी विस्फोटक सवाल हवा में तैर रहे हैं। और तीसरी तरफ पार्टी के भीतर से आती आवाजें भी शामिल है कि मेरा नम्बर कब आएगा।

पॉवर का ट्रेंगिल

जिस पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत अनुशासन रही है उसी के भीतर अगर पार्टी के नेता अपने सम्मान हिस्सेदारी उपेक्षा और अवसर की बात सार्वजनिक मंचों पर करने लगें तो सवाल केवल एक नेता का नहीं रह जाता। लखनऊ से कौशल किशोर का मामला इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका जवाब भी बनता है। वरिष्ठ नेता केन्द्र मोदी सरकार में राज्यमंत्री रह चुके पूर्व सांसद कौशल किशोर ने 13 सितंबर को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आत्मसम्मान रैली का ऐलान किया है। उनका कहना है कि उन्हें पार्टी के भीतर लंबे समय से जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। उनकी पत्नी जोकि योगी सरकार में विधायक है ने भी गंभीर आरोप लगाये थे कि उन्हें मंदिर में पूजा करने का मौका नहीं दिया गया। यह घटना सिर्फ उदहारण के लिए है ऐसे अनेकों नेता है जो अब खुलकर सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयान कर रहे हैं वह नेता चाहे राज्य स्तरीय हो या फिर बड़े नेता। इन दिनों पार्टी के भीतर बगावत का रिहर्सल चलने जैसा प्रातीत हो रहा है और शायद कैबिनेट रिशफल इनही सब चीजों को देखकर किया जा रहा है।

अगले दौर की राजनीति का नक्शा पढ़ा जा सकता है

भाजपा संगठन में बदलाव के बाद कैबिनेट में बदलाव की चर्चा इसी कारण सामान्य प्रशासनिक फेरबदल से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है। केंद्र में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संवैधानिक सीमा 81 है और 69 मंत्री होने के कारण 12 संभावित मंत्रियों का स्पेस बनता है यानी विस्तार की गुंजाइश भी मौजूद है।

अपने ही नेता के आत्म सम्मान रैली से हिल गयी सरकार

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद कौशल किशोर ने कहा कि उन्हें जानबूझकर अपमानित किया गया है और 13 सितंबर को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होने वाली आत्मसम्मान रैली सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि आजादी के शहीदों, सनातन धर्म रक्षकों और कम वेतन पर काम कर रहे संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों के सम्मान के लिए है। इस आत्मसम्मान रैली का आयोजन पासी महासंघ के बैनर तले किया जा रहा है। सांसद कौशल किशोर ने कहा, आउटसोर्सिंग और संविदा की यह प्रथा आत्मसम्मान को झकझोरती है। यह लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा है और इसे खत्म होना चाहिए। यह रैली संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए है। 13 सितंबर को लखनऊ के दुबग्गा स्थित जॉगर्स पार्क के पास बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर यह आत्मसम्मान रैली आयोजित की जाएगी।

कई मुद्दों को लेकर सरकार की साख पर सवाल

बाहर जेन जी सवाल पूछ रहा है, युवा नौकरी मांग रहा है, भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं किसान का सवाल है, कहीं संविदा कर्मचारी अपने भविष्य की बात कर रहा है, और उसी समय पार्टी के भीतर सांसद कह रहे हैं कि सम्मान चाहिए अवसर चाहिए हिस्सेदारी चाहिए। तो क्या कैबिनेट फेरबदल इन तमाम सवालों का जवाब बन सकता है शायद नहीं लेकिन यह राजनीतिक संदेश जरूर बन सकता है और भाजपा यह जानती है कि राजनीति में संदेश कभी कभी फैसले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जातें हैं। क्योंकि युवाओं को संकेत देना है कि नई पीढ़ी आ रही है महिलाओं को संकेत देना है कि प्रतिनिधित्व बढ़ेगा राज्यों को संकेत देना है कि उनका वजन बरकरार है पुराने नेताओं को संकेत देना है कि भूमिका खत्म नहीं बदल सकती है और नाराज सांसदों को संकेत देना है कि दरवाजा बंद नहीं हुआ है यही वह उम्मीद है जिसके सहारे पार्टी के भीतर बेचैनी को नियंत्रित रखा जा सकता है कि सबको मौका मिलेगा।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

संवैधानिक संस्थाओं पर चोट मतलब लोकतंत्र पर हमला

आजादी के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात के आरोपों के कारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन संस्थाओं के कामकाज के तौर–तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन पर पूरी तरह से सत्तारुढ केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के इशारों पर काम करने करने और विपक्ष के अधिकारों को दबाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

सरकार के कई कामों पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल केवल विपक्ष ही नहीं आम जनता की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। जिसका परिणाम जेनजी का आंदोलन था। अब ये चर्चा खास व जनता में आम हो गई है देश में समय के साथ लोकतंत्र के परिपक्व होने के बजाए कमजोर होने की आहट आ रही है। आजादी के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात के आरोपों के कारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन संस्थाओं के कामकाज के तौर–तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन पर पूरी तरह से सत्तारुढ केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के इशारों पर काम करने करने और विपक्ष के अधिकारों को दबाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों के इस घेरे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़, भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक और अब मुख्य चुनाव आयुक्त आ चुके हैं। लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 118 विपक्षी सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। विपक्षी सांसदों का दावा था कि ओम बिरला ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार दिखाया है और उनका कार्यालय अपेक्षित निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहा है।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका पर चर्चा हुई है और कई बार मेरा नाम लिया गया, मेरे बारे में गंदी बातें कही गईं। उन्होंने कहा कि यह सदन भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। यह सदन किसी एक पार्टी का नहीं है, यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी हम बोलने के लिए उठते हैं, हमें बोलने से रोक दिया जाता है। पिछली बार जब मैंने बात की थी, तब मैंने हमारे प्रधानमंत्री के किए गए समझौतों के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाया था। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 51प्रतिशत थी। नेशनल एवरेज 66प्रतिशत था। 16वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 52 प्रतिशत थी। नेशनल एवरेज 80 प्रतिशत था। 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 43प्रतिशत थी, जबकि नेशनल एवरेज 76 प्रतिशत था। उन्होंने कुछ सदस्यों की शिकायतों पर भी बात की कि उन्हें माइक्रोफोन की दिक्कतों की वजह से बोलने नहीं दिया गया। शाह ने कहा कि जो कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा या सदन में अनुशासन बनाए नहीं रखेगा, उसका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाएगा और कहा कि संसद की कार्यवाही इसी तरह चलनी चाहिए। तो अब आम जनता भी पूछ रही है कि क्या दबंगई से सरकार संसद को चलाएगी।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

कागजों की जांच-पड़ताल से बड़ा है मताधिकार

विवेक शर्मा

मतदाता सूची को सही रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मृत लोगों के नाम हटने चाहिए। जो लोग कहीं और चले गए हैं, उनका रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। एक व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज है तो उसे भी सुधारा जाना चाहिए। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सही और भरोसेमंद बनाना है। लेकिन इस काम के बीच आम मतदाता इतना न उलझ जाए कि उसे अपने ही मताधिकार को लेकर चिंता होने लगे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली में एसआईआर को लेकर गहमागहमी है। सभी जगह इसकी प्रक्रिया एक साथ नहीं चल रही। पुराने मतदाता रिकॉर्ड का इस्तेमाल सत्यापन के लिए किया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 2002 की मतदाता सूची महत्वपूर्ण है, जबकि पंजाब में 2003 की सूची को आधार बनाया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में यह प्रक्रिया बाद के चरण में होगी। मुश्किल यह है कि 2002 या 2003 आज से करीब ढाई दशक पुरानी बात है। उस समय की हर जानकारी हर परिवार के पास सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं। इतने वर्षों में लोग घर और शहर बदल चुके हैं। कई परिवार दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं। पुराने सरकारी रिकॉर्ड में नाम की वर्तनी, उम्र या पते में अंतर भी हो सकता है। ऐसे में पुराने और मौजूदा रिकॉर्ड का पूरी तरह मेल न खाना अपने आप में किसी मतदाता को गलत साबित नहीं करता। दिल्ली में करीब 33 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आई हैं। इनमें करीब 14 लाख मतदाताओं का विवरण 2002 की एसआईआर सूची से नहीं जुड़ पाया, जबकि करीब 19 लाख मामलों में अन्य विसंगतियां मिली हैं। इनमें मौजूदा और पुराने रिकॉर्ड में नाम की वर्तनी अलग होने जैसे मामले भी शामिल हैं। इन मतदाताओं को अपनी पात्रता स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा। पंजाब के पूर्व राजनयिक नवदीप सूरी का मामला इस परेशानी को समझने का एक उदाहरण है। वर्ष 2003 में वह भारत में नहीं थे, बल्कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात थे।

पंजाब में एसआईआर के दौरान उनका मौजूदा विवरण 2003 के पुराने मतदाता रिकॉर्ड से नहीं मिल पाया। उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस मिला। हालांकि उनका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं गया था। बाद में यह मामला सुलझ गया। फिर भी सवाल महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति उस समय देश में ही नहीं था, उससे उस समय की मतदाता सूची में अपने नाम का मिलान कैसे कराया जाए? प्रक्रिया में ऐसी परिस्थितियों के

लिए स्पष्ट और आसान रास्ता होना चाहिए। यह परेशानी केवल किसी पूर्व राजनयिक की नहीं है। देश में लाखों लोग नौकरी, कारोबार या दूसरे कारणों से वर्षों तक एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं। कई परिवारों ने पुराने घर छोड़ दिए। कई लोग दूसरे राज्यों में बस गए। ऐसे में करीब 24 साल पुराने रिकॉर्ड को आज की पहचान से जोड़ना हमेशा आसान नहीं हो सकता। सरकारी रिकॉर्ड में भी गलतियां हो सकती हैं। नाम की वर्तनी बदल सकती है। पते में अंतर हो सकता है। इसलिए जहां नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जानकारी सही दे और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत करे, वहीं सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी भी है कि वह अपने पास मौजूद रिकॉर्ड से तथ्यों की पुष्टि करे। एसआईआर का विरोध करना समाधान नहीं है। साफ और सही मतदाता सूची हर चुनाव की पहली जरूरत है। लेकिन सही सूची बनाने का अर्थ यह भी है कि कोई पात्र मतदाता केवल इसलिए बाहर न रह जाए क्योंकि 2002 या 2003 के रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं मिला या उसकी जानकारी में मामूली अंतर था। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपना नाम मतदाता सूची में जांचना चाहिए। कोई गलती या कमी हो तो तय समय में दावा या आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन को भी यह प्रक्रिया इतनी सरल रखनी होगी कि आम आदमी उसे आसानी से समझ सके और पूरा कर सके। पुराने रिकॉर्ड की जानकारी न होने को केवल नागरिक की गलती मान लेना उचित नहीं होगा। मतदाता सूची में एक गलत नाम रह जाना समस्या है, लेकिन एक सही मतदाता का नाम गलती से बाहर हो जाना उससे बड़ी समस्या है।

जांच कड़ी हो, लेकिन तरीका मानवीय हो। दस्तावेज मांगे जाएं, लेकिन उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड की भी मदद ली जाए। लोकतंत्र में मतदाता किसी फाइल का एक नंबर नहीं है। वह उस व्यवस्था का केंद्र है। उसके वोट से सरकार बनती है और उसकी भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए मतदाता सूची को साफ करने की कोशिश में यह ध्यान रखना होगा कि कागजों की कमी या पुराने रिकॉर्ड की विसंगति के बीच असली मतदाता कहीं पीछे न छूट जाए।

भीड़ में भी अकेले होने की वैश्विक त्रासदी

डॉ. रितु सारस्वत

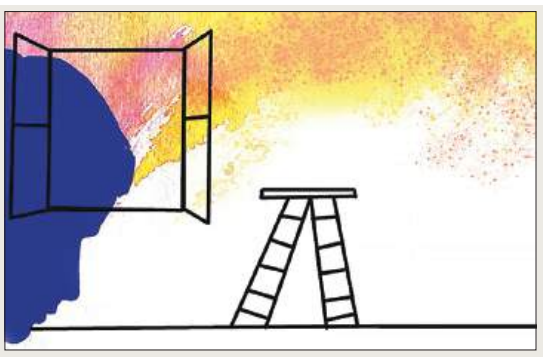

हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने सोशल मीडिया पर अपने कार्यालय का एक अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि रात में काम करते हुए उन्हें वहां एक कॉकरोच दिखाई दिया। उन्होंने स्वयं उसे नहीं मारा और कुछ समय तक वह वहीं रहा। बाद में जब उनके स्टाफ ने उसे हटा दिया, तो उन्होंने लिखा—'राहत तो मिली, लेकिन थोड़ा अकेलापन और उदासी भी महसूस हुई।''लेकिन थोड़ा अकेलापन और उदासी भी महसूस हुई' ये वे पंक्तियां हैं, जो मन में हजारों प्रश्नों को जन्म देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि क्या हम सब कहीं न कहीं बहुत अकेले हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि लोगों से भरी इस दुनिया में भी किसी एक की कुछ पलों की मौजूदगी हमारे अकेलेपन को भर देती है और उसकी अनुपस्थिति फिर उसी अकेलेपन का एहसास करा जाती है? क्या मनुष्य के लिए साथ की जरूरत केवल तब होती है, जब वह सचमुच अकेला हो, या भीड़ के बीच भी किसी अपने की उपस्थिति उतनी ही जरूरी होती है?

दरअसल, हम सभी एक बहुत बड़े असत्य को सत्य मान बैठे हैं और वह यह कि जो व्यक्ति प्रभुत्वशाली है, धनी है या फिर जो प्रसिद्ध है, वही इस संसार में सबसे सुखी है। सुख की हमारी यह परिभाषा हमें निरंतर एक ऐसी दौड़ में ले जाती है, जहां हम उपलब्धियों की ऊंचाइयों को ही जीवन की सार्थकता मान बैठे हैं। लेकिन क्या सचमुच जीवन में किसी मुकाम को हासिल कर लेना व्यक्ति को भीतर से वह खुशी, आत्मसंतोष और तृप्ति दे देता है, जिसकी तलाश में वह इस पूरी दौड़ में शामिल होता है? फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपनी फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद के एक अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि उस उपलब्धि की खुशी के बीच एक क्षण ऐसा आया, जब उनके मन में सवाल उठा मैं आज रात क्या करूं? किसके घर जाऊं? किसका हाथ थामूं? मुझे खुशी महसूस करने के लिए पीठ पर एक छोटी-सी थपकी की जरूरत थी और मैं उसे चाहता था।

उपलब्धि का यह क्षण अपने आप में बताता है कि खुशी का पूरा अर्थ उसे किसी के साथ साझा करने में ही है। अकेलापन केवल इस बात से तय नहीं होता कि हमारे आसपास कितने लोग हैं। असल सवाल यह है कि उन लोगों के बीच हम स्वयं को कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हमारे जीवन में ऐसे संबंधों की जरूरत होती है, जहां हम अपनी खुशी बांट सकें, अपने दुख को कह सकें और बिना किसी संकोच के अपने मन की बात रख सकें। शायद इसी वजह से भीड़ के बीच भी अकेलेपन का अनुभव उतना ही वास्तविक हो सकता है, जितना बिल्कुल अकेले रहने पर। इसी मानवीय आवश्यकता को अब वैश्विक स्तर पर भी गंभीरता से समझा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सोशल कनेक्शन पर गठित आयोग की रिपोर्ट 'फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन = चार्टिंग अ पाथ टू हेल्दियर सोसाइटीज' बताती है कि सामाजिक अलगाव और अकेलापन व्यापक समस्या बन चुके हैं और उनका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, कल्याण और समाज पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। रिपोर्ट सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए ठोस और व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले उपायों की आवश्यकता पर जोर देती है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में लगभग हर छह में एक व्यक्ति अकेलेपन का अनुभव करता है और यह समस्या किसी एक उम्र या समाज तक सीमित नहीं है।

विशेष रूप से किशोरों और युवाओं में इसका प्रसार अधिक है। रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि मजबूत सामाजिक संबंध केवल व्यक्ति के सुख और कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि उसके स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और व्यापक सामाजिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये तो वे आंकड़े हैं, जो दर्ज किए गए हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं व्यापक है। सच यह है कि हम सभी भीड़ में कहीं न कहीं बहुत अकेले हैं और शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अकेलेपन को महसूस न किया हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस गंभीर प्रश्न पर चिंता व्यक्त की है, उस पर दशकों पूर्व 'द लोनली क्राउड' में सार्थक चर्चा की गई थी। 1950 में प्रकाशित यह पुस्तक आधुनिक समाज में व्यक्ति के सामाजिक जीवन और उसके भीतर बढ़ते अकेलेपन के विभिन्न पहलुओं को सामने लाती है। 'द लोनली क्राउड' बताती है कि लोगों के बीच रहना अपने आप में व्यक्ति को अकेलेपन से मुक्त क्यों नहीं कर पाता और सामाजिक जीवन का विस्तार होने के बावजूद व्यक्ति भीतर से अलग-थलग क्यों महसूस कर सकता है।

पुस्तक इस विरोधाभास की ओर संकेत करती है कि व्यक्ति समाज और भीड़ का हिस्सा होते हुए भी अपने भीतर एक ऐसे अकेलेपन का अनुभव कर सकता है, जिसे केवल लोगों की मौजूदगी से दूर नहीं किया जा सकता। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि जीवन में सफलता, उपलब्धि और एक मुकाम हासिल कर लेने के बाद व्यक्ति को किसी के साथ की जरूरत कम हो जाती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमिस्टर और मार्क लीरी के 1995 के शोध-पत्र 'द नीड टू बिलॉन्ग डिजायर फॉर इंटरपर्सनल अटैचमेंट्स ऐज अ फंडामेंटल ह्यूमन मोटिवेशन' ने इस धारणा को एक अलग दृष्टिकोण दिया है। उनके अनुसार, मजबूत और स्थायी मानवीय संबंध बनाना और उन्हें बनाए रखना मनुष्य की एक मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। जीवन में हम किसी भी मुकाम पर क्यों न पहुंच जाएं, हमारे भीतर ऐसे संबंधों की जरूरत बनी रहती है।

कहीं आप भी तो नहीं हैं रिंगजाइटी का शिकार

मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं दुनियाभर के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं। कम उम्र के लोग भी स्ट्रेस-एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कतों का शिकार देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मेंटल हेल्थ का ठीक रहना, पूरी सेहत को ठीक रखने के लिए जरूरी माना जाता है। आमतौर पर लोग शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा अलर्ट रहते हैं, पर इसकी तुलना में मानसिक स्वास्थ्य पर कम ध्यान देते हैं। जबकि कई अध्ययनों में ये साबित हो चुका है कि मेंटल हेल्थ में किसी भी तरह की गड़बड़ी का असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है।

* *एंग्जायटी यानी घबराहट होना, तनाव या किसी अनिश्चित स्थिति के प्रति शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसके कारण दिल की धड़कन तेज होने से लेकर, सांस फूलने और जरूरत से ज्यादा पसीना आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एंग्जाइटी वैसे तो बहुत कॉमन समस्या है, पर क्या आपने रिंगजाइटी के बारे में सुना है?*
* *स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, रिंगजाइटी की समस्या युवाओं में तेजी से बढ़ती जा रही है। रिंगजाइटी शब्द रिंग और एंग्जाइटी से मिलकर बना है। इसमें व्यक्ति को अक्सर लगता रहता है कि उसका फोन बज रहा है या उसमें नोटिफिकेशन आया है? पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। क्या आप भी इस तरह की समस्याओं का अनुभव करते हैं?*

फैंटम रिंगिंग या फैंटम फोन सिंगल्स की समस्या

* मेडिकल साइंस में रिंग्जाइटी को फैंटम रिंगिग या फैंटम फोन सिंगल्स भी कहा जाता है। इसमें केवल ऐसा नहीं लगता है कि फोन की घंटी सुनाई दे रही है बल्कि फोन के वाइब्रेट होने या नोटिफिकेशन आने का एहसास भी हो सकता है। जबकि वास्तिवकता में न तो फोन बज रहा होता है और न ही कोई नोटिफिकेशन आया होता है।
* स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, लेकिन लगातार फोन से लगे रहने वाले लोगों में या किसी की कॉल का इंतजार करते समय ये समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है।
* साल 2016 के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों में अटैचमेंट एंग्जाइटी (रिश्तों के टूटने या प्रियजनों द्वारा छोड़े जाने का अत्यधिक डर) रहती है, उनमें फैंटम रिंगिग की शिकायत ज्यादा देखी गई।

क्यों होती है ये समस्या?

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ सत्यकांत त्रिवेदी बताते हैं, रिंग्जाइटी को मानसिक बीमारी नहीं माना जाता। यह तब होता है जब लगातार स्मार्टफोन के इस्तेमाल करने की वजह से दिमाग शरीर की सामान्य संवेदनाओं को फोन के वाइब्रेशन समझ लेता है। हालांकि नोटिफिकेशन कम करके, बार-बार फोन चेक करने को लेकर खुद को कंट्रोल करने के अलावा तनाव को मैनेज करके इस आदत में सुधार किया जा सकता है। रिंग्जाइटी का एक ही कारण तय नहीं है। इसका संबंध फोन के लगातार इस्तेमाल, किसी कॉल या मैसेज का इंतजार और किसी चिंता की प्रतिक्रिया हो सकता है। जिन लोगों को किसी व्यक्ति के जवाब, कॉल या संपर्क को लेकर ज्यादा चिंता रहती थी, उनमें यह अनुभव अधिक हो सकता है। रिंग्जाइटी को आमतौर पर गंभीर नहीं माना जाता है, पर अगर इसके कारण आपकी दिनचर्या में दिक्कत होने लगे या फिर काम बाधित होने लगे तो इस बारे में विशेषज्ञ की सलाह ले लें। संभव है कि इसके पीछे मेंटल हेल्थ की कोई और दिक्कत हो?

इससे बचने के लिए क्या करें?

मनोचिकित्सक कहते हैं, ये मेंटल हेल्थ की कोई समस्या नहीं है। रिंग्जाइटी की दिक्कत से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में सुधार जरूरी है।

सबसे जरूरी कदम है खुद से फोन का इस्तेमाल कम करना। हर कुछ मिनट में फोन चेक करने की आदत कम करें और गैर-जरूरी नोटिफिकेशन बंद करें। सोने के समय फोन को बिस्तर से दूर रखना भी लगातार फोन पर ध्यान जाने से बचा सकता है। यदि आप किसी जरूरी कॉल का इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो फोन को हर समय हाथ में रखने की जरूरत नहीं है। तनाव और चिंता कम करने के लिए नियमित नींद, शारीरिक गतिविधि, आराम और स्क्रीन से ब्रेक लेना मददगार हो सकता है। हालांकि अगर आपको फैंटम रिंगिग की दिक्कत बार-बार हो रही है और इससे बेचैनी, नींद या रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं, तो मनोचिकित्सक से सलाह जरूर ले लें।

हंसना मना है

रीमा: तुम अपनी मांग में हरे रंग का सिन्दूर क्यूं लगाती हो? सीमा: मेरे पति रेलवे में इंजन ड्राइवर है। जब मैं लाल सिन्दूर लगाती हूं तो वह मुझे देखकर रुक जाते हैं। इसलिए मैं हरा सिन्दूर लगाती हूं ताकि वह मुझे देखकर आगे बढ़ जायें!

पत्नी: तुम आज रात के खाने मे क्या खाना चाहोगे? पति खुश होते हुए: मुझे सरप्राइज कर दो ! पत्नी: ठीक है, मैंने रात का खाना छुपा दिया है इसे ढूंढों...

पति: तुम गाड़ी चलाते समय जीपीएस के साथ बहस क्यों करती रहती हो? पत्नी: क्योंकि यह मुझे, तुम्हारी तरह बताने की कोशिश करता रहता है कि कहां जाना है !

पति: तुम्हें पता है, तुम एक बेहतरीन अलार्म घड़ी बना सकती हो। पत्नी: सच? ऐसा क्यों? पति: क्योंकि तुम मुझे हमेशा तब जगाती हो जब मैं उठना नहीं चाहता !

अपनी शादी की सालगिरह पर। पत्नी: प्रिये, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं ! पति परेशान होकर: मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है की जैसे सदियों बीत गए हो।

कहानी | बूढ़ा आदमी युवा पत्नी और चोर

किसी ग्राम में किसान दम्पती रहा करते थे। किसान तो वृद्ध था पर उसकी पत्नी युवती थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी सदा पर-पुरुष की टोह में रहती थी, इस कारण एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वह एकान्त में पहुँच गई तो उसके सम्मुख जाकर उसने कहा,देखो, मेरी पत्नी का देहान्त हो चुका है। मैं तुम पर अनुरक्त हूं। मेरे साथ चलो। वह बोली, यदि ऐसी ही बात है तो मेरे पति के पास बहुत-सा धन है, वृद्धावस्था के कारण वह हिलडुल नहीं सकता। मैं उसको लेकर आती हूं, जिससे कि हमारा भविष्य सुखमय बीते। ठीक है जाओ। कल प्रात:काल इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की स्त्री अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया, तो उसने अपने पति का धन समेटा और उसे लेकर प्रात:काल उस स्थान पर जा पहुंची। दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने ग्राम से बहुत दूर निकल आए थे कि तभी मार्ग में एक गहरी नदी आ गई। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा। और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया तो वैसे भी संकट ही है। अत: किसी प्रकार इससे सारा धन हथियाकर अपना पिण्ड छुड़ाना चाहिए। यह विचार कर उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है। पहले मैं गठरी को उस पार रख आता हूं, फिर तुमको अपनी पीठ पर लादकर उस पार ले चलूंगा। दोनों को एक साथ ले चलना कठिन है। ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की स्त्री ने अपनी गठरी उसे पकड़ाई तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने-कपड़े भी दे दो, जिससे नदी में चलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और कपड़े भीगेंगे भी नहीं। उसने वैसा ही किया। उन्हें लेकर ठग नदी के उस पार गया तो फिर लौटकर आया ही नहीं। वह औरत अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही।

सीख : अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए।

8 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

चौथे भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी प्रोजेक्ट्स और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स को विशेष पहचान और सम्मान मिलेगा।

वृषभ

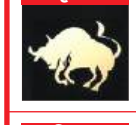

पंचम भाव का उच्च बुध शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या पूर्व में किए गए स्मार्ट निवेश से अप्रत्याशित मुनाफा करा सकता है। पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से अटके हुए भुगतानों की वसूली में गति आएगी।

मिथुन

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बैंक बैलेंस को मजबूत करने और धन संचय के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। पुष्य नक्षत्र के शुभ प्रभाव से अटका हुआ पुराना धन वापस मिलने के प्रबल आसार हैं।

कर्क

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन धन प्रवाह और आर्थिक सुदृढ़ता के लिहाज से बेहद फलदायी रहेगा। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से भूमि, वाहन या अचल संपत्ति में किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा।

सिंह

घर-परिवार में पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा। परिवार के किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान पर चर्चा हो सकती है।

कन्या

घर-परिवार में उत्सव, सुख-शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूर्ण समर्थन मिलने से आपका मनोबल ऊंचा रहेगा।

तुला

घर-परिवार में सुख, शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा। पिता व घर के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन मिलने से मन में उत्साह बना रहेगा।

वृश्चिक

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता का स्तर आज बहुत उत्कृष्ट रहेगा। नवम भाव में चंद्रमा-गुरु का प्रभाव पुरानी मानसिक बेचैनी, थकान और तनाव को पूरी तरह समाप्त करेगा।

धनु

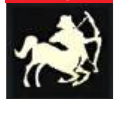

घर-परिवार में पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से आध्यात्मिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता आएगी और उनका सहयोग प्राप्त होगा।

मकर

आज का दिन संयुक्त प्रयासों और बौद्धिक सौदों से धन लाभ कमाने का है। नवम भाव में उच्च का बुध और सप्तम भाव में गजकेसरी योग पूर्व में किए गए किसी निवेश या व्यावसायिक पार्टनरशिप से बड़ा मुनाफा करा सकते हैं।

कुम्भ

घर-परिवार में पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से शांति, अनुशासन और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ स्वास्थ्य या छोटी-मोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें।

मीन

घर-परिवार में आनंद, सुख और आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा। संतान पक्ष से कोई उत्साहवर्धक समाचार या उपलब्धि मिलने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ेगी।

बॉलीवुड | प्रशंसा

वरुण धवन ने फिल्म हनुमान अंश की जमकर की तारीफ

हनुमान अंश ने जहां एक तरफ अपनी कमाई से सबको हैरान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसकी जमकर तारीफ भी हो रही है। फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। जानिए अब वरुण धवन का फिल्म को लेकर क्या कहना है। रविवार को वरुण धवन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि उन्होंने अपनी मां के साथ थिएटर में जाकर 'हनुमान अंश' देखी। उन्होंने कहा, कृपया थिएटर जाएं और 'हनुमान अंश' देखें। मैं अभी अपनी मां के साथ यह फिल्म देखने गया था और यह एक शानदार अनुभव रहा। अपने माता-पिता को साथ लेकर जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं। मैं सभी को इस फिल्म को देखने की सलाह देता हूं। उन्होंने आगे कहा, मुझे यह वीडियो बनाने के लिए किसी ने नहीं कहा था और न ही किसी ने मुझे फोन किया था। मैं बस खुद यह करना चाहता था। बचपन से ही मेरा भगवान हनुमान से एक जुड़ाव रहा है, लेकिन यह फिल्म कुछ अलग ही है। यह पूरी तरह से दिल से बनाई गई फिल्म है। मैं तो इसे फिल्म भी नहीं कहूंगा, यह कुछ दिव्य है। आप थिएटर जाएं और खुद इसका अनुभव करें। वरुण ने आगे फिल्म के निर्देशन और कलाकारों की परफॉर्मेंस की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, शोभिनाव सत्याजी फिल्म में शानदार हैं। क्या परफॉर्मेंस है। और विशा जी, आपने जिस तरह से फिल्म का निर्देशन किया है, उसके लिए आपको सलाम। शानदार काम है। कृपया सभी लोग जाएं और यह फिल्म जरूर देखें। 'हनुमान अंश' को विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में शोभिना डब्ल्यू. सत्य, विहान एस. हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के. रस्तोगी और गुलशन पांडे जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। फिल्म को रागिनी एस., नम्रता जी. सिंह, अनुप्रिया ए. नगर और विशाल चतुर्वेदी ने प्रोड्यूस किया है।

20 साल बाद बड़े पर्दे पर शाहरुख खान संग नजर आएंगी रानी मुखर्जी

इस साल की मोस्ट अवेटेड बॉलीवुड मूवी के बारे में बात की जाए तो उसमें शाह रुख खान स्टारर फिल्म किंग का नाम शामिल है। पठान जैसी सफल फिल्म बनाने वाले निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की किंग की कास्ट को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

बताया जा रहा है कि हिंदी की एक दिग्गज अभिनेत्री 20 साल बाद शाह रुख खान के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन सी एक्ट्रेस से हैं, जो किंग फिल्म में नजर आएंगी।

लंबे समय से शाह रुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर पर मूवी की कास्ट को लेकर अक्सर अलग-अलग खबरें सामने आती रहती हैं। फिलहाल मिड डे की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार रानी मुखर्जी शाह रुख खान की किंग में नजर आएंगी।

रिपोर्ट के मुताबिक किंग फिल्म में रानी अभिनेता अभिषेक बच्चन के

अपोजिट नजर आएंगी। आखिरी बार रानी और अभिषेक साल 2007 में आई फिल्म लागा चुनरी में दाग में एक साथ नजर आए थे। इसके अलावा किंग खान के साथ रानी मुखर्जी की आखिरी फिल्म कभी अलविदा न कहना थी, जो 2006 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

अब किंग फिल्म के जरिए रानी मुखर्जी अपने दो पुराने को-स्टार शाह रुख खान और अभिषेक बच्चन संग दोबारा से काम करती दिख सकती हैं। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी इस मामले की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन रानी का नाम सामने से किंग फिल्म को लेकर फैंस के बीच हाइप और अधिक बढ़ गई है।

बता दें कि शाह रुख खान स्टारर किंग को इसी साल 24 दिसंबर यानी क्रिसमस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। अगर रानी मुखर्जी वास्तव में शाह रुख खान की किंग का हिस्सा बनती हैं तो इससे मूवी की कास्ट और अधिक बड़ी हो जाएगी। क्योंकि उनसे पहले दीपिका पादुकोण, सौरभ शुक्ला, सुहाना खान, राघव जुयाल, अनिल कपूर, जयदीप अहलवात और जैकी श्रॉफ जैसे कई कलाकारों के नाम सामने आ चुके हैं।

अनमोल टीवी के शो 'हमारी राधा' में राधा और शनाया की अनजाने में हुई मुलाकात!

देखिए 'हमारी राधा' हर रात 9: 30 बजे, सिर्फ अनमोल टीवी पर

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज़ेस लिमिटेड के फ्री-टू-एयर (एफटीए) हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल अनमोल टीवी के पहले ओरिजिनल शो 'हमारी राधा' में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुँचने वाली है, जहाँ राधा (सिमरन कौर) और शनाया (वैदेही नायर) पहली बार अनजाने में एक-दूसरे के सामने आएँगी। लेकिन, राधा को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि शनाया का उसके पति गिरधर (अक्षय म्हात्रे) से बेहद खास रिश्ता है। दोनों की अनजाने में हुई यह मुलाकात धीरे-धीरे ऐसा मोड़ ले लेगी, जिसका असर आगे की कहानी पर देखने को मिलेगा। दरअसल, शनाया खरीदारी करने जाती है और बिलिंग काउंटर पर उसे पता चलता है कि गिरधर का कार्ड अपनी लिमिट पार कर चुका है। इसी बीच राधा भी उसी स्टोर में पहुँच जाती है। खरीदारी के दौरान शनाया का कार्ड गलती से गिर जाता है, जिसे राधा और गिरधर का बेटा कियान उठा लेता है। कियान देखते ही अपने पिता का कार्ड पहचान लेता है। लेकिन, शनाया कियान पर ही कार्ड चुराने का आरोप लगा देती है और देखते ही देखते दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है।

राधा जब वहाँ पहुँचती है और अपने बेटे पर चोरी का इल्ज़ाम लगते देखती है, तो वह तुरंत अपने बेटे के बचाव में खड़ी हो जाती है। वह शनाया से माफ़ी माँगने के लिए कहती है और तब तक पीछे नहीं हटती, जब तक शनाया कियान से माफ़ी नहीं माँग लेती। राधा अपने बेटे का साथ देते हुए अपनी बात पर अड़ी रहती है। इस तरह यह मुलाकात अचानक ऐसी बहस में बदल जाती है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राधा के सामने खड़ी शनाया के बारे में वह भले ही अभी कुछ नहीं जानती, लेकिन दोनों की अनजाने में हुई यह मुलाकात आगे आने वाली कई परेशानियों का सीधा इशारा है। अब जब दोनों एक-दूसरे के सामने आ चुकी हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि जब राधा को शनाया और गिरधर के रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी, तब क्या होगा।

अजब-गजब | ये हैं भारत के सबसे खतरनाक मंदिर

इन मंदिरों में पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं

भारत में मंदिरों की कमी नहीं है. देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे मंदिर हैं, जो अपनी आस्था के साथ-साथ इतिहास, रहस्य और अनोखी लोकेशन के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ मंदिर शहरों के बीचों-बीच बने हैं, तो कुछ ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए जंगल, पहाड़ और बेहद कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि इन जगहों की यात्रा आम मंदिरों के दर्शन से बिल्कुल ही अलग अनुभव देती है। आज हम ऐसे ही 3 मंदिरों की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है। क्योंकि यहां जाना आसान नहीं है फिर भी लोग भारी संख्या में यहां पहुंचते हैं। आइए जानते हैं , इन मंदिरों के बारे में और लोग क्यों यहां भारी संख्या में पहुंचते हैं, इसके पीछे का कारण।

दरअसल, जिन मंदिरों की हम बात कर रहे हैं, उनमें मध्य प्रदेश का ककनमठ मंदिर रामाकोना के पास स्थित राघा देवी मंदिर और महाराष्ट्र के नासिक के पास हरिहर फोर्ट पर स्थित मंदिर शामिल हैं। हालांकि, इन जगहों को खतरनाक कहने का मतलब यह है कि इनके रास्ते या आसपास का इलाका कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इन मंदिरों से जुड़ी मान्यताएं।

ककनमठ मंदिर: देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्मारक, महल और किले हैं, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और इतिहास के लिए मशहूर हैं। इन्हीं में से एक है मुरैना जिले के सिहोनिया में स्थित ककनमठ मंदिर, जिसे स्थानीय

स्तर पर 'भूतों का मंदिर' भी कहा जाता है। यह प्राचीन मंदिर अपनी अनोखी बनावट और इससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापत्य कला 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास की मानी जाती है, यानी यह करीब एक हजार साल पुराना है। मंदिर विशाल पत्थरों से बनाया गया है और इसकी खास बात यह है कि पत्थरों को जोड़ने में चूना, मिट्टी या सीमेंट जैसे मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया। मंदिर आज भले ही काफी हद तक खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसकी दीवारों, छतों और स्तंभों पर बनी देवी-देवताओं और पौराणिक आकृतियों की नक्काशी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। मंदिर में गर्भगृह, स्तंभयुक्त मंडप और मुखमंडप भी मौजूद हैं।

श्री राघा देवी मंदिर: श्री राघा देवी मंदिर (जिसे आमतौर पर रागा देवी या राघादेवी गुफा मंदिर भी कहा जाता है) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रामाकोना के पास स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, यहां भगवान शिव का स्वयंभू (प्रकट) शिवलिंग मौजूद है। यह मंदिर जमीन से लगभग 20 से 30 फीट नीचे एक गुफा के भीतर स्थित है, यहां जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए इस चमत्कारी गुफा में छिपे थे और यहीं से पचमढ़ी की ओर गए थे। ऐसी भी मान्यता है कि इस गुप्त गुफा का रास्ता पचमढ़ी तक जाता है। इस मंदिर को भारत के खतरनाक मंदिरों की सूची में शामिल किया गया है।

हरिहर फोर्ट, नासिक: हरिहर फोर्ट, जिसे हरिहरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह किला अपनी बेहद खड़ी और कठिन चढ़ाई के लिए जाना जाता है। यहां पहाड़ को काटकर करीब 90 डिग्री के कोण पर पत्थर की सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिन पर चढ़ना काफी मुश्किल होता है। किले तक पहुंचने का रास्ता भी कई जगह संकरा और चुनौतीपूर्ण है, इसलिए यहां चढ़ाई के दौरान काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। समुद्र तल से करीब 3676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले तक पहुंचना शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किले के अंदर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी स्थित है, जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। चढ़ाई कठिन होने के बावजूद श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। यही वजह है कि हरिहर फोर्ट का मंदिर आस्था के साथ-साथ रोमांच और कठिन यात्रा के लिए भी जाना जाता है।

भारत के इस गांव में रहते हैं सिर्फ 17 परिवार बिना बिजली-मोबाइल के जीते हैं अपनी लाइफ!

आज की दुनिया में हर कोई स्मार्टफोन, बिजली, इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव है जहां लोग जानबूझकर इन सभी चीजों से दूर रहकर वैदिक शैली में जीवन जी रहे हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित कुर्मा ग्रामम या कुर्माग्राम वैदिक विलेज में सिर्फ17 परिवार रहते हैं। यहां ना बिजली है, ना मोबाइल नेटवर्क, ना टीवी और ना ही एलपीजी सिलेंडर। इस गांव में लोग मिट्टी और चूने से बने घरों में रहते हैं, अरण्डी के तेल के दीयों से रोशनी करते हैं और लकड़ी या गोबर के उपलों से खाना पकाते हैं। यह गांव आधुनिक तरक्की के बीच सादगी और आध्यात्मिकता का अनोखा उदाहरण पेश करता है। कुर्मा ग्रामम करीब 60 एकड़ में फैला हुआ है। यह एंथकापल्ली की पहाड़ियों के बीच बसा है और श्रीकाकुलम शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। गांव की स्थापना 2018 के आसपास नंदा गोकुलम गोशाला ट्रस्ट के तहत हुई थी। यह इस्कॉन के संस्थापक ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं से प्रेरित है। यहां के निवासी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के सिद्धांत पर चलते हैं। इस गांव के लोग आधुनिक सुविधाओं को छोड़कर प्रकृति और वैदिक परंपराओं के करीब रहना चाहते हैं। सुबह तीन-साढ़े तीन बजे ब्राह्म मुहूर्त में गांव जाग जाता है। लोग दीये की रोशनी में नहा-धोकर प्रार्थना हॉल में इकट्ठा होते हैं। वहां आरती, भजन और योग होता है। बच्चों को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती है जिसमें संस्कृत, वेद, भागवत गीता, रामायण और महाभारत शामिल हैं। साथ ही तेलुगु, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान भी सिखाया जाता है। दिन भर खेती-बाड़ी, गोशाला की देखभाल, कपड़े बुनने और घर के कामों में बीतता है। शाम सात-साढ़े सात बजे तक लोग सो जाते हैं क्योंकि बिजली ना होने से अंधेरा हो जाता है। घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और चूने से बनाए जाते हैं। सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल नहीं होता। फर्श गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है जिसे बैक्टीरिया से सुरक्षा मिलती है। हर घर में अपना कुआं होता है। खाना लकड़ी के चूल्हे पर पकता है। साबुन की जगह रीठा या प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल होती हैं। कपड़े खुद हाथकरघा पर बनाए जाते हैं। खेती पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से की जाती है। कोई रासायनिक खाद या कीटनाशक नहीं डाला जाता। अनाज, सब्जियां और फल खुद उगाए जाते हैं जिससे गांव आत्मनिर्भर बना रहता है। गांव में एक गोशाला भी है जहां गायों की सेवा होती है। गायों का दूध, गोबर और मूत्र सभी काम में आता है। निवासी कहते हैं कि यह जीवन तनाव मुक्त है। स्क्रीन की चमक, नोटिफिकेशन की आवाज और शहर की भागदौड़ यहां नहीं है। लोग प्रकृति की लय में जीते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त उनके समय को निर्धारित करते हैं।

अभिषेक उपाध्याय की बहादुरी ने छुड़ाये यूपी सरकार के पसीने !

रोड रेज के मामले में पत्रकार का डिजिटल रिकॉर्ड क्यों खंगाल रही पुलिस?

सुप्रीम कोर्ट के सवालों से बेहाल यूपी पुलिस, मांगा जवाब

» राम मंदिर में दान अनियमितताओं का मुद्दा उठाने वाले पत्रकार की याचिका पर सुनवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। एक रोड रेज के मामले की जांच के लिए किसी पत्रकार के सोशल मीडिया और डिजिटल फुटप्रिंट की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल पर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस से जवाब मांगा है। मामला लखनऊ के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय से जुड़ा है जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में दान से संबंधित अनियमितताओं को लेकर खबरें की थीं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ अभिषेक उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन भी शामिल थे।

उपाध्याय ने गाजियाबाद पुलिस की ओर से 18 अगस्त की रोड रेज की घटना को लेकर दर्ज एफआईटार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह बात आई कि गाजियाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पत्रकार के जून 2026 से अब तक के डिजिटल फुटप्रिंट से जुड़ी जानकारी मांगी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से साफ तौर पर पूछा कि जब जांच रोड रेज की घटना की हो रही है तो पत्रकार के डिजिटल फुटप्रिंट की आवश्यकता क्यों है? अदालत ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि एक्स से आखिर किस तरह की जानकारी मांगी गई है और उसका रोड रेज की एफआईआर या पत्रकार के खिलाफ दर्ज किसी अन्य मामले की जांच से क्या संबंध है।

अभिषेक उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक उपाध्याय को राहत देते हुए साफ किया है कि 25 अगस्त को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। इस मामले का दायरा केवल एक रोड रेज एफआईआर तक सीमित नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से अब बड़ा सवाल यह सामने आया है कि आपराधिक जांच के नाम पर पुलिस किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया रिकॉर्ड और डिजिटल गतिविधियों को किस सीमा तक खंगाल सकती है। खास तौर पर तब जब मामला एक पत्रकार से जुड़ा हो और वह सरकार या अन्य संस्थाओं से जुड़े संवेदनशील विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहा हो। अदालत यदि इस मामले में डिजिटल फुटप्रिंट जुटाने को लेकर स्पष्ट मानक या दिशा-निर्देश तय करती है तो भविष्य में पुलिस जांच डिजिटल निजता और पत्रकारों के अधिकारों के लिहाज से इसका व्यापक असर पड़ सकता है।

निजता के अधिकार का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल डेटा जुटाने के मामले में निजता के अधिकार का सवाल भी उठाया। अदालत का कहना था कि जांच एजेंसियों को जांच का अधिकार है। लेकिन इसके साथ आरोपी की निजता और पीड़ित के अधिकारों के बीच भी संतुलन जरूरी है। अदालत अब इस बात पर विचार करेगी कि किसी व्यक्ति के डिजिटल फुटप्रिंट जुटाने की सीमा और उसके लिए जरूरी मापदंड क्या होने चाहिए। अदालत ने फिलहाल यह भी निर्देश दिया है कि डिजिटल फुटप्रिंट से संबंधित जो भी जानकारी एकत्र की गई है उसे अगली सुनवाई तक सार्वजनिक नहीं किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शरण देव सिंह ठाकुर अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ मानहानि की शिकायतों से जुड़े दो अन्य मामलों की भी जांच चल रही है।

शारीरिक सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं अभिषेक

सरकार की तरफ से अदालत को यह भी बताया गया कि रोड रेज मामले में एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान है और पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। सरकार का कहना है कि जांच में पत्रकार के खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिलता है तो मामला बंद कर दिया जाएगा। अभिषेक उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय और अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी ने पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि ऐसे मामलों में पुलिस किस हद तक किसी व्यक्ति का डिजिटल डेटा हासिल कर सकती है इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए। उपाध्याय ने अपनी याचिका में रोड रेज मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही वैकल्पिक मांग की गई है कि यदि एफआईआर रद्द नहीं होती है तो मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दी जाए। याचिका में पत्रकार ने अपनी गिरफ्तारी और शारीरिक सुरक्षा को लेकर भी आशंका जताई है। उनका आरोप है कि प्रभावी न्यायिक संरक्षण मिलने से पहले उन्हें राज्य की मशीनरी से जुड़े लोगों के माध्यम से नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

टीएमसी सांसद अभिषेक को राहत

» स्वास्थ्य शिविरों में एफआईआर मामले में गिरफ्तारी पर 30 नवंबर तक रोक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों से जुड़े मामले में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी और उनके खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे मामलों पर नाराजगी भी जताई। इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने बनर्जी के खिलाफ कुल चार प्राथमिकियों से जुड़े दो मामलों में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी थी। सोमवार को जिन मामलों में बनर्जी को राहत मिली, उनमें उनके द्वारा आयोजित दो 'सेवाश्रय' स्वास्थ्य शिविरों में चिकित्सा लापरवाही और इलाज में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह 30 नवंबर तक बनर्जी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।

अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी और उसी दिन संबंधित पुलिस अधिकारी इन प्राथमिकी की जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि एक ही व्यक्ति ने एक से अधिक मामलों में पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। सुनवाई के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि वह ऐसा आदेश जारी करेंगे, जिसके बाद उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना बनर्जी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकेगी। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने मौखिक टिप्पणी में कहा, अब बहुत हो गया। इस साल मई से मैं इन मामलों की सुनवाई कर रहा हूं।अब मैं एक अन्य पीठ द्वारा शुभेंदु अधिकारी से जुड़े मामले में दिए गए आदेश के आधार पर निर्देश जारी करूंगा, जिसमें कहा गया था कि अदालत की अनुमति के बिना उनके (अधिकारी) खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए।

राज्य का दर्जा बहाली पर केंद्र से संपर्क जारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने सहित केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के बीच लंबित मुद्दों के समाधान के लिए वह लगातार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं। उमर ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में जम्मू-कश्मीर द्वारा अपने पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ''मैं गृहमंत्री के लगातार संपर्क में हूं। जम्मू-कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और केंद्र के बीच कुछ मामले लंबित हैं, जैसे राज्य का दर्जा बहाल करना, कामकाज के नियमों को मंजूरी देना, महाधिवक्ता की नियुक्ति में लगभग दो साल की देरी, और आरक्षण से जुड़ी वह रिपोर्ट जिसे केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा पहले उठाए गए सवालों का जवाब देने के बाद भी केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है। उमर ने नयी दिल्ली में शाह से हुई हालिया मुलाकात के सवाल पर कहा, ''इन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक मस्जिद को हटाए जाने के सवाल पर कहा कि

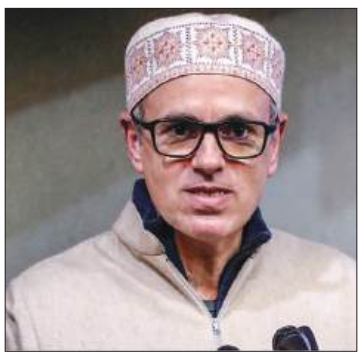

» यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में मुसलमानों के साथ 'सौतेला' व्यवहार किया जा रहा है: सीएम उमर

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में मुसलमानों के साथ 'सौतेला' व्यवहार किया जा रहा है। उमर ने कहा, ''उनके नेता बयान देते हैं कि मुसलमान समाज का अभिन्न अंग हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसी घटनाएं होती हैं। नएस्थान तलाशें वे अपने ही नेताओं की बात नहीं मानते।'' मुख्यमंत्री ने सोमवार को शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कहा कि यह देश के फिल्मकारों को याद दिलाता है कि स्विट्ज़रलैंड और दूसरी विदेशी जगहों पर जाने से पहले कश्मीर शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा जगह थी।

तेलंगाना विधानसभा स्पीकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल

» बीआरएस एमएलसी थाथा मधुसूदन और एन. नवीन कुमार रेड्डी हिरासत में

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हैदराबाद। तेलंगाना विस के अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के दो विधान परिषद सदस्यों एमएलसी को गिरफ्तार किया गया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि थाथा मधुसूदन और एन. नवीन कुमार रेड्डी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया।

तिहरा शतक नहीं लगा सके ईशान किशन

» दलीप ट्रॉफी फाइनल में बतौर कप्तान दोहरा शतक के मामले में की गायकवाड़ की बराबरी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। दलीप ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन भी ईस्ट जोन के बल्लेबाजों का दम दिखा। कप्तान ईशान किशन भले ही तिहरा शतक नहीं लगा सके, लेकिन उनकी शानदार पारी के बदौलत ईस्ट जोन ने साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ईस्ट जोन की पहली पारी समाप्त होने के साथ ही दूसरे दिन का खेल खत्म होने की घोषणा कर दी गई। ईस्ट जोन के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान ईशान किशन ने 334 गेंदों पर 30 चौकों और सात छक्के की मदद से 270 रन बनाकर आउट हुए।

उनके अलावा कुमार कुशाग्र ने 132 गेंदों पर आठ चौकों और पांच छक्कों के सहारे 101 रन की पारी खेली। शुरुआती दो दिन ईस्ट जोन के बल्लेबाजों का दम देखने मिला। दूसरे दिन ईशान रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन बाद में वह फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे। हालांकि, साउथ जोन की टीम दिन का खेल समाप्त होने तक ईस्ट जोन की पारी खत्म करने में सफल रही।

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन की कप्तानी करते हुए ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। 270 रन की तूफानी पारी के साथ ईशान अब दलीप ट्रॉफी फाइनल में यह कारनामा करने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। रविवार को पहले दिन का खेल खत्म होने तक शतक लगाकर नाबाद लौटे ईशान ने दूसरे दिन भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही ईशान किशन ने 39 साल पुराना एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। 1987-88 में वेस्ट जोन की कप्तानी करते हुए अंशुमान गायकवाड़ ने फाइनल में 216 रन बनाए थे। अब ईस्ट जोन के कप्तान ईशान ने 250 रन की पारी (रिटायर्ड हर्ट) खेलकर बतौर कप्तान दोहरा शतक के मामले में गायकवाड़ की बराबरी तो की ही, पर बतौर कप्तान दलीप ट्रॉफी के फाइनल में व्यक्तिगत स्कोर के मामले में उनसे आगे निकलकर रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।

महिला एशिया कप: श्रीलंका ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश

दुबई। श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2026 के 10वें मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ चार विकेट से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। श्रीलंकाई टीम इस टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाकर ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर रही। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी बांग्लादेशी टीम ने निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 114 रन बनाए। शोभना मोस्तरी ने शोर्ना अख्तर (9) के साथ चौथे विकेट के लिए 40 गेंदों में 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के बेहद करीब पहुंचाया। शोभना ने टीम के लिए सर्वाधिक 34 रन बनाए। 41 गेंदों की पारी में उनके बल्ले से चार चौके निकले। इसके जवाब में श्रीलंका ने 19.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया।

गलती से भी सोनी का टीवी मत लेना, रो पड़ोगे !

क्रोमा से खरीदारी की गलती भी मत करना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। यदि आप टीवी खरीदने निकले हैं तो जरा ठहर जाइए कहीं ऐसा न हो कि दुकान से सोनी कंपनी का महंगा ओएलईडी टीवी लेकर घर आएं और कुछ ही हफ्तों बाद टीवी की जगह सर्विस सेंटर के चक्कर काटते रह जाएं। एक ग्राहक की शिकायत ने सोनी के प्रीमियम टीवी और क्रोमा की आफटर सेल सर्विस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब इतना बढ़ चुका है कि ग्राहक ने सोनी इंडिया और क्रोमा इंफिनिटि रिटेल लि. को सिर्फ 24 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया है कि अब न मरम्मत चाहिए न रिप्लेसमेंट और न सोनी का कोई दूसरा टीवी हमे पूरा पैसा ब्याज सहित वापस चाहिए।

पूरा मामला Sony OLED BRAVIA 8 II, मॉडल नंबर 55XR80M2 का है जिसे शिकायतकर्ता मनीष मौर्या ने 7 जून 26 को मुंबई के अंधेरी स्थित क्रोमा स्टोर से खरीदा था। शिकायतकर्ता के मुताबिक करीब एक महीने के भीतर ही टीवी में गंभीर तकनीकी खराबी सामने आ गई। सोनी के अधिकृत तकनीशियन ने टीवी की जांच और मरम्मत की लेकिन समस्या दोबारा पैदा हो गई। इसके बाद टीवी पूरी तरह बंद हो गया। इस मामले में सोनी कंपनी के पास दो सर्विस रिक्वेस्ट भी दर्ज कराई गयी जिनका शिकायत क्रम इस प्रकार है INCA2601200847 और INCA 2601532036।

पूरा मामला सोनी ओएलईडी ब्राइवा का

टीवी आपका, पैसा मेरा पूरा वापस करो

शिकायतकर्ता ने अपने पहले कानूनी नोटिस में रिफंड रिपलेसमेंट का विकल्प रखा था लेकिन अब ग्राहक ने रिपलेस्मेंट का विकल्प वापस लेते हुए केवल फुट रिफंड चुना है। पत्र में टीवी की पूरी इन्वाईस/परचेज प्राइज लागू ब्याज सहित लौटाने की मांग की गई है। मनीष मौर्या का कहना है कि पहले कानूनी नोटिस में 30 लाख रुपये के मुआवजे और हर्जाने की मांग की गई थी और फुल रिफंड मांगने से यह दावा खत्म नहीं होगा। उन्होंने असुविधा सेवा में कमी, मानसिक परेशानी, व्यावसायिक कार्य में बाधा और कानूनी खर्च समेत अन्य दावों को सुरक्षित रखने की बात कही है। मनीष ने दोनों कंपनियों को 24 घंटे की डेडलाइन दी है। मांग की गई है कि इस अवधि में लिखित रूप से फुट रिफंड मंजूर किए जाने और उसकी प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि की जाए तथा रकम लौटाने की निश्चित समयसीमा बताई जाए।

बहुत हुआ पैसा रिफंड करो

मनीष मौर्या के मुताबिक उसकी सहमति से सोनी के अधिकृत प्रतिनिधि खराब टीवी को जांच और सर्विस के लिए अपने साथ ले गए। एक सप्ताह गुजर गया लेकिन टीवी वापस नहीं आया और समाधान भी नहीं मिला। यानी जिस प्रीमियम टीवी के लिए हमने ने पूरी कीमत चुकाई वह खरीद के महज तीन महीने के भीतर लंबे समय से उसके इस्तेमाल में ही नहीं है। मनीष ने सोनी और क्रोमा को भेजे अपने ताजा शिकायती पत्र में साफ शब्दों में कहा है कि वह टीवी की मरम्मत स्वीकार नहीं करेगा। रिप्लेसमेंट भी नहीं चाहिए। सोनी का दूसरा मॉडल भी नहीं चाहिए। उनका कहना है कि बार बार खराबी और पहले किए गए सर्विस प्रयास के बाद वह इस लेन-देन को आगे जारी नहीं रखना चाहता।

तमिलनाडु विस में हंगामा, डीएमके और टीवीके सरकार में वार-पलटवार

» मार्शल ने विधायकों को सदन से निकाला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया जब द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के उस बयान को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की जिसमें उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। द्रमुक विधायकों ने इसके साथ ही नारेबाजी की, जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल के कई विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही द्रमुक के सचेतक ई वी वेलु ने सोमवार को विजय द्वारा दिए गए बयान का हवाला देते हुए मांग की कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मुख्यमंत्री के संदर्भों को सदन के रिकॉर्ड से हटाया जाए, क्योंकि यह सदन के नियमों के विरुद्ध है। वेलु ने सरकारिया आयोग के संदर्भों पर भी आपत्ति जताई और कहा कि आयोग ने माना था कि कोई अपराध नहीं हुआ था।

कानून मंत्री आर. निर्मल कुमार ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट और ईडी के आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर मुख्यमंत्री के बयान का बचाव किया। उन्होंने तत्कालीन द्रमुक सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को भी दोहराया। द्रमुक सदस्यों ने इसका विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष जे सी डी प्रभाकर ने मुख्यमंत्री की टिप्पणियों को सदन के रिकॉर्ड से हटाने की मांग खारिज कर दी, जिसके बाद द्रमुक विधायकों की नारेबाजी जारी रही।

आखिर कर दी न लल्लन ने ओछी हरकत

» लल्लन टॉप ने शहीन/नफीसा का इंटरव्यू तो किया लेकिन 4पीएम का नाम लिये बिना

» 4पीएम की कामयाबी से जल रहा लल्लन टॉप, बीजेपी की बी टीम बनता जा रहा है चैनल!

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। इंडिया टुडे ग्रुप का वेब मीडिया हाउस लल्लन टॉप ने पत्रकारिता के नाम पर ऐसी ओछी हरकत की है कि मीडिया में काम करने वाले लोग खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की 4पीएम रिपोर्टर शाहीन और नफीसा के साथ हुए पुलिसिया जुल्म की कहानी तो लल्लनटॉप ने उठायी लेकिन पूरी रिपोर्ट में कही भी 4पीएम का नाम नहीं लिया। रिपोर्ट में शहीन नफीसा को 4पीएम सवांददाता नहीं बताया गया।

अगर आप को ऐसा करना था तो फिर इंटरव्यू क्यों लिया? और खबर उठाई तो यह बताने में शर्म क्यों आई कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? शहीन/नफीसा प्रकरण को लेकर अब मीडिया के भीतर ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मामले को लगभग सभी बड़े टीवी चैनलों और वेब न्यूज प्लेटफॉर्म ने गंभीरता से उठाया। लल्लनटॉप ने भी शहीन नफीसा का इंटरव्यू किया, खबर को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी और दर्शकों तक मामला पहुंचाया।

खबर सिर्फ कंटेंट नहीं होती

पत्रकारिता की दुनिया में खबर सिर्फ कंटेंट नहीं होती उसके पीछे रिपोर्टर की मेहनत जोखिम और स्रोत तक पहुंच भी होती है। खासकर तब जब किसी संवेदनशील मामले को सबसे पहले जमीन पर मौजूद रिपोर्टर सामने लाता है। यह सवाल पत्रकारिता की उस संस्कृति पर है जहां दूसरे की मेहनत से तैयार हुई खबर को उठाकर व्यूज तो हासिल किए जाएं लेकिन क्रेडिट देने के वक्त कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया जाए। क्योंकि खबर उठाना पत्रकारिता हो सकती है लेकिन खबर की जड़ बताना पत्रकारिता की ईमानदारी है। और सवाल यही है कि शहीन/नफीसा की कहानी में 4पीएम का नाम आखिर गायब क्यों था?

पत्रकारिता की आत्मा को ठेस पहुंचाई है लल्लन टॉप ने

लल्लन टॉप ने पूरी कवरेज में उस मूल पत्रकारिता का उल्लेख तक नहीं किया गया जिसके बाद यह मामला व्यापक मीडिया विमर्श का हिस्सा बना। 4पीएम ने इसी को लेकर लल्लनटॉप पर तीखा हमला बोला है। 4पीएम का कहना है कि दूसरे संस्थान शहीन नफीसा को 4पीएम की रिपोर्टर के तौर पर पहचान दे रहे थे तब लल्लनटॉप ने अपनी पूरी स्टोरी में 4पीएम का नाम लेने से परहेज क्यो किया। अगर किसी संस्थान ने किसी रिपोर्टर की मेहनत और उसके द्वारा सामने लाई गई खबर को आधार बनाकर अपनी स्टोरी तैयार की है तो कम से कम पत्रकारिता की बुनियादी ईमानदारी यह मांग करती है कि मूल रिपोर्टिंग का क्रेडिट दिया जाए। पूरा मामला क्रेडिट तक सीमित नहीं है अब सवाल लल्लनटॉप की पत्रकारिता की दिशा पर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि लल्लनटॉप लगातार अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है और उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 4पीएम की बढ़ती पहुंच और कामयाबी से लल्लनटॉप खुद को असहज महसूस कर रहा है और इसी वजह से उसके कवरेज में 4पीएम को श्रेय देने से बचने की कोशिश दिखाई देती है।

योगी सरकार से सवाल पूछा तो हुदा जरीवाला हुई गिरफ्तार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सरकार के फैसले पर सवाल पूछना क्या अब अपराध बन गया है? सत्ता की कार्रवाई पर असहमति जताना क्या कानून-व्यवस्था के लिए खतरा माना जाएगा? और अगर किसी सामाजिक कार्यकर्ता की बात सरकार को असहज करती है तो उसका जवाब तर्क और तथ्य से दिया जाएगा या फिर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा? सहारनपुर में सामाजिक कार्यकर्ता हुदा जरीवाला की गिरफ्तारी के बाद यही सवाल तेजी से उठने लगे हैं। मामला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को हटाने की कार्रवाई से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक हुदा जरीवाला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहारनपुर के जिलाधिकारी को लेकर सोशल मीडिया और सार्वजनिक तौर पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ टिप्पणी की।

अधिवक्ता दुष्यंत सिंह की शिकायत पर सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने उन्हें शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन इस कार्रवाई का दूसरा पहलू भी है क्या सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को भड़काऊ बताकर चुप कराया जा सकता है। हुदा जरीवाला के खिलाफ पुलिस का आरोप अभी जांच का विषय है। पुलिस का कहना है कि उनके एक वीडियो के सामने आने के बाद शिकायत की गई और शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि टिप्पणियों से क्षेत्र की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था के बीच की रेखा पर बहस शुरू होती है।

» मस्जिद पर कार्रवाई के बाद उठी आवाज पर पुलिस का पहरा

» सवालों का जवाब नहीं, गिरफ्तारी क्यों?

» टिप्पणी के नाम पर सामाजिक कार्यकर्ता पर कार्रवाई क्या असहमति अब शांतिभंग हो गई?

भाजपा नेता हैं पीजी माफिया के असली मालिक : आप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने से सात मौतों के बाद,आप ने भाजपा नेताओं पर पीजी माफिया होने का गंभीर आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि इलाके के पेइंग गेस्ट मकानों के असली मालिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और सरकार जानबूझकर मालिकों की सूची जारी नहीं कर रही।

आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में चल रहे पेइंग गेस्ट (पीजी) मकानों के असली मालिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं।

महिला पत्रकारों से कथित मारपीट के विरोध में पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन

» पत्रकार सुरक्षा आयोग के गठन समेत कई मांगें उठाईं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

उरई। नई दिल्ली में समाचार संकलन के दौरान 4पीएम की महिला पत्रकारों शाहीन खान एवं नफीसा खान के साथ पुलिस द्वारा कथित मारपीट एवं अभद्रता के विरोध में मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, जनपद जालौन के पदाधिकारियों एवं पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

जिलाध्यक्ष मनोज राजा के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जनहित से जुड़े मुद्दों को समाज और शासन-प्रशासन के सामने लाने का कार्य करते हैं। ऐसे में समाचार संकलन के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। विशेष रूप से महिला पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा